कर दिये जाने के कारण स्कूल का समय नष्ट होता है तथा बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए किये गये अध्ययन तथा उपायों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत इस समय केवल छह राज्य और एक संघशासित प्रदेश गर्म पका हुआ भोजन प्रदान कर रहे हैं। इस विभाग का विचार है कि इस योजना के अन्तर्गत पका हुआ भोजन प्रदान करने के लिए शिक्षकों को भाग नहीं लेना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए दिशा-निर्देशों में, गरीबी निवारण कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदान की गई निधि में से रसोइए के रूप में लगे व्यक्तियों के वेतन के भुगतान के लिए प्रावधान किए गए हैं। तदनुसार जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ऐसे भुगतानों को सम्मिलित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

Facilities at Ernakulam North Railway Station

3057. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the facilities at Ernakulam North railway station are inadequate; and

(b) if so, the steps taken to improve the facilities including the expansion of Building and Platform II?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) Facilities at stations are provided according to norms based on the volume of traffic handled. Facilities commensurate with the volume of traffic has already been provided at Ernakulam Town station.

(b) Does not arise. There is no proposal for expansion of station building at present. Extension of shelter on platform No 2 was completed recently.

ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु उपाय

3058. **श्री इकबाल सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने देश की ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने, उन्हें रोजगार दिलाने तथा उनमें व्याप्त निर्धनता को कम करने के लिए अब तक क्या-क्या प्रभावी उपाय किये हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ वर्ष 1996-97 के बजट में कोई धनराशि आवंटित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई): (क) से (ग) भारत सरकार अन्य लोगों के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उनमें व्याप्त निर्धनता को कम करने के लिए निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रम चला रही है:—

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	बजट प्राक्कलन (1996-97)
1.	समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों में कम से कम 40 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए।	639.85
2.	जवाहर रोजगार योजना इस योजना के तहत कम से कम 30 प्रतिशत रोजगार महिलाओं को दिये जाते हैं।	1865.00
3.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास	65.00
4.	महिला समृद्धि योजना	60.00
5.	स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण	14.00
6.	प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम सहायता हेतु	16.00
7.	सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम	6.00

8.	महिलाओं के लिए रोजगार तथा आयोत्पादक प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र स्थापित करना	18.00

इसके अतिरिक्त, 31 करोड़ रुपए की कोर्पस राशि से 1993 में स्थापित किया गया राष्ट्रीय महिला कोष निर्धन महिलाओं को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Setting up of professional colleges

3059. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether a number of professional colleges, medical and engineering have been set-up in Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Orissa, Andhra Pradesh and Karnataka, this year;

(b) if so, the total number of sets created in engineering and medicine thereby in the country in each state; at the entrance stage;

(c) the steps taken to ensure uniformity in standard of professional education;

(d) whether any capitation fee or other such charges are leviable for admission in such courses; if so, the details in this regard; and

(e) the number of seats reserved therein for Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) to (e) All India Council for Technical Education (AICTE) a statutory body has approved the engineering courses in the following new institutions indicating therewith their annual intake during 1996-97:—

Name of the State	Number of Institutions	Intake capacity
Maharashtra	4	740
Gujarat	3	420
Madhya Pradesh	5	790
Orissa	2	300
Andhra Pradesh	8	1300
Karnataka	Nil	Nil

AICTE has laid down norms and standards for degree colleges of engineering which are required to be followed by all concerned. The approved institutions are monitored regularly. AICTE has also laid down regulations on the basis of the Supreme Court judgement given in the Unnikrishnan case for admission and fees for private unaided professional colleges. As provided in the AICTE Regulations the reservation of seats is as per the policy of the State Government or the Central Government as the case may be.

As far as medical colleges are concerned, none has been set up in these States during this year i.e. 1996-97.

Financial support for Soil Conservation in Orissa

3060. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have been extending financial support to the State Governments to implement soil conservation scheme for reclamation of ravine land;

(b) if so, the fund allocated to Orissa for implementing this scheme during the Eighth Plan; and

(c) the details of the eroded land in different areas of Orissa where conservation measures have been undertaken during the said plan period?